Rajasthan, Government will consider the desirability of locating this project somewhere in that State and thus give an impetus to the wool breeding programme which will considerably ameliorate the economy of the poor tribals and other weaker sections in that State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SUPPLY AND TEXTILES (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH): (a) and (b) A Study group was appointed to study the problems of wool and woollen Industry. In its Report, the Study Group had *inter-alia*, recommded constitution of a Wool Board. An Inter-Ministerial 'Empowered Committee' under the Chairmanship of Secretary (Textiles) was constituted by the Government to take decisions for effective and expeditious implementation of the recommendation made in the said Report. The decisions of the Empowered Committee have been finalised recently, and the Committee has decided to constitute a Wool Board for an integrated development of the Woollen Textile Industry.

(c) Wool Board is constituted for integrated and harmonious development of all the sectors of Woollen Textile Industry. Its location would be decided keeping in view the requirements and convenience of all sectors of Woollen Textile Industry.

हिन्दी सलाहकार समिति का गठन

13. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी तक हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया है, यदि हां तो इसके क्या कारण है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि आवश्यक हिन्दी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की अनुमति नहीं दी जा रही है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) जी, नहीं। एक संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के स्थान पर दो अलग-अलग हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। एक व्यय विभाग और राजस्व विभाग के लिए और दूसरी बैंकिंग और बीमा सहित आर्थिक कार्य विभाग के लिए।

(ख) वित्त मंत्रालय के तीनों विभागों में से प्रत्येक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पदनाम के आधार पर की जाती है।

(ग) जनवरी, 1984 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मुद्रा-स्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में आगामी आदेशों तक वर्तमान रिक्तियों को न भरने की सलाह दी गई थी। तथापि, इन आदेशों के अन्तर्गत निम्न पद से पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा रिक्तियों को भरने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अन्तर्गत 550-800/- रु० और ऊपर के ग्रेड में हिन्दी पद कुल मिलाकर निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा भरे जाते हैं। इसलिए इस सीमा तक इन ग्रेडों में रिक्तियों को भरे जाने में कोई कठिनाई नहीं है।

टसर और मूंगा रेशम का निर्यात

14. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलबरी रेशम के मुकाबले टसर और मूंगा रेशम का निर्यात हुआ है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी रेशम के निर्यात के मामले में स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि टसर और मूंगा रेशम के निर्यात में गिरावट इसके कम उत्पादन के कारण आई है; यदि हां, तो सरकार इनका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ;

(ग) क्या यह सच है कि टसर और मूंगा किस्मों का रेशम केवल, बिहार, मध्य प्रदेश और असम के राज्यों में उपलब्ध है जहां तक रेशम